>

Title: Need to provide honorarium and other benefits to Anganwadi workers of Andaman and Nicobar Islands as per the orders of the Central Government.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, दिनांक 14.12.2009 को मैंने शून्य प्रहर में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के आंगनवाड़ी के वर्कर एवं हैल्पर आदि के बारे में अपनी बात रखी थी। उसके मुताबिक दिसंबर, 2009 में प्रशासन को पत्र भी लिखा था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारे अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में एक आदमी पर साल में पचास हजार रूपये खर्च होते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं हैल्पर के वैलफेयर फण्ड के नाम पर सन् 2001 में भारत सरकार ने प्रशासन को आदेश दिया कि आप इनके वैलफेयर फण्ड के लिए कुछ काम करें। वेलफेयर फण्ड को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर को 60 साल बाद पेंशन दी। तमिलनाडु सरकार ने उनको पे-स्केल दिया और पेंशन भी दे रही है। रिटायरमेंट के बाद लम्पसम 50 हजार रूपये वर्कर के लिए और हैल्पर के लिए 20 हजार रूपये देते हैं। केरल गवर्मेंट दस साल के बाद पेंशन दे रही है। कर्नाटक सरकार पेंशन दे रही है। पुडुचेरी, जहां से हमारे मंत्री जी नारायणसामी जी आते हैं, वहां पर पुडुचेरी कार्पोरेशन आंगनवाड़ी हैल्पर को पेंशन देता है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह ने आज तक पेंशन नहीं दी है। सरकारी संस्था है एनिटको, उसका काम शराब की बिक्री करना है, और कुछ नहीं करना है।

एनिटको के माध्यम से पुडुचेरी कार्पोरेशन जैसे इन वर्कर्स को पेंशन दे रहा है। यह मांग लेकर मैंने पत्र भी दिया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि हमारे द्वीपसमूह में आंगनबाड़ी वर्कर्स, हैल्पर, मिनी वर्कर्स कुल मिलाकर 1,373 हैं, इन लोगों को पेंशन दें, इन्हें परमानेंट करें। आंगनबाड़ी बीमा योजना की बहुत बुरी हालत है। बीमा योजना भारत सरकार ने अप्रैल 2004 से शुरू की, बाकी राज्यों में बीमा योजना शुरू है, बीमा योजना में कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों को पढ़ने के लिए 300 रूपये मिलेंगे, लेकिन आज तक बीमा योजना शुरू नहीं हुई है। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में प्री-स्कूल किड्स को चार्ट खरीदने के लिए एक हजार रूपये सालाना, लेकिन चार साल में एक बार किट्स मिलता है। आईईसी(अवेयरनेस) के लिए सालाना हर आंगनबाड़ी के लिए एक हजार रूपया सैंशन है, लेकिन एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यूनीफॉर्म देने के लिए साल में दो जोड़ के लिए 400 रूपया मिलना चाहिए, लेकिन वह भी नहीं मिला। आंगनबाड़ी हैल्पर्स को बैच मिलना चाहिए था, वह भी नहीं मिला। गांवों में आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए सरकार 200 रूपये किराया देगी, लेकिन वह अंडमान में अमल नहीं हुआ। अर्बन एरिया में जो आंगनबाड़ी सेंटर्स चलते हैं, उनको घर के लिए 750 रूपये मिलने हैं, लेकिन वह पांच-छह महीने बाद मिलता है। फ्लैक्सी फंड, मामूली खर्चे के लिए, आंगनबाड़ी सेंटर के लिए जैसे कोई चार्ट खरीदना, दरी खरीदने आदि के लिए हजार रूपये सेंटर को मिलना तय हुआ, लेकिन वह आज तक लागू नहीं हुआ है। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 750 रूपये मिलते हैं, वहां 19 सेंटर्स हैं। भारत सरकार ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि आंगनबाड़ी हैल्पर को कम से कम 1500 रूपये ऑनरेरियम मिलेगा, लेकिन आज तक वह भी नहीं मिला है। मैं मांग करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत सरकार के अंडर में है, लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। इसीलिए अण्णा हजारे जी की बात सही है। अण्णा हजारे जी वही बात बोलते हैं कि सिटीजन चार्टर बनाओ। लोकसभा को क्या करना है, एम.पी. की चिट्ठी पर कार्यवाही नहीं होती है, जीरो ऑवर में उठाए गए विषयों पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोगों को प्रोटैक्शन कहां से मिलेगा? अण्णा हजारे जी की बात सही है, अण्णा हजारे जी का जन-लोकपाल बिल होने से सिटीजन चार्टर होता और लोगों को यह अधिकार मिलने वाला था। पवन कुमार बंसल जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह भारत सरकार के अंडर में है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप सब लोग हैं तो उसकी हालत ऐसी क्यों है? तमिलनाडु गवर्नमेंट पेंशन देगी, कर्नाटक गवर्नमेंट पेंशन देगी, क्या आप लोगों के पास अंडमान में पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं? आप बोलते हैं कि यह आम आदमी की सरकार है। मैं मांग करता हूं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की समस्याओं का तुरन्त समाधान कीजिये। इस मांग के लिए मैं दोबारा जीरो ऑवर में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अगली बार जीरो ऑवर में मौका न मिलने पर मैं क्या करूंगा, मुझे स्पीकर महोदया के सामने जाकर वैल में बैठना पड़ेगा। मेरे पास बस यही रास्ता है। जय हिन्द, भारत माता की जय।

अध्यक्ष महोदया : आप वैल में मत बैठियेगा।

â€¦(व्यवधान)